उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्, रामनगर (नैनीताल)	इण्टरमीडिएट परीक्षा 'अ' (उत्तराखण्ड) 12 पन्ने

केन्द्र संख्या की मुहर	केन्द्र व्यवस्थापक के हस्ताक्षर	नोट—परीक्षार्थी उत्तरपुस्तिका के किसी भी भाग में अपना

'उत्तर-1(क)'

रूस के पहले चुने हुए राष्ट्रपति थे - बोरिस येल्तसिन

'उत्तर-1 ख'

मालदीव गणतंत्र बना - ~~2005~~ 1968 में
2005 में संविधान बनाया,

'उत्तर-1 ग'

'मार्शल योजना' शुरू की - अमेरिका

'उत्तर-1 घ'

अमेरिका के साथ 'सामरिक अस्त्र परिसीमन संधि 2' पर हस्ताक्षर किए गए - सोवियत संघ

'उत्तर-1 ङ'

1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर भारत में कितने राज्य व केन्द्रशासित प्रदेश बने - 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदे

'उत्तर-1 च'

शिमला समझौते पर हस्ताक्षर - 1972

'उत्तर-1 छ'

'संसद मार्च' का नेतृत्व किया - जयप्रकाश नारायण

'उत्तर-1 ज'

बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक - कांशीराम

'उत्तर-1 झ'

A तथा R दोनों सही हैं R, A की सही व्याख्या नहीं करता,

'उत्तर-1 ञ'

A सही है तथा R गलत है,

'उत्तर-2'

संयुक्त राष्ट्रसंघ के मूल संस्थापक सदस्यों की संख्या 51 थी,

'उत्तर-3'

भारत ने वर्ष 2002 में 'क्योटो प्रोटोकाल पर हस्ताक्षर किए,

'उत्तर - 4'

बार्बी डाल का निर्माण अमेरिका ने किया,

'उत्तर - 5'

भारतीय जनसंघ का गठन 1951 में हुआ, इसके संस्थापक अध्यक्ष श्यामप्रसाद मुखर्जी थे,

'उत्तर - 6'

प्रिवी पर्स की समाप्ति 1971 के आम चुनाव के समय की गई, इंदिरा गांधी द्वारा की गई।

'उत्तर - 7'

मण्डल आयोग द्वारा सरकारी नौकरियों में पिछड़ी जाति के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की गई थी,

'उत्तर - 8'

यूरोपीय संघ के झण्डे में 12 सोने के रंग के सितारों का घेरा है जो एकता का प्रतीक है। बारह के अंक को वहां पारंपरिक रूप से समग्रता, सम्पूर्णता और एकता का प्रतीक माना जाता है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है।

P.T.O

'उत्तर-9'

अंतर्राष्ट्रीय आण्विक ऊर्जा एजेन्सी की स्थापना 1957 में की गई, ~~इसकी~~ इसके सदस्य देश 171 तथा इसका मुख्यालय विएना आस्ट्रिया में है।

कार्य-(i) परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना
(ii) सैन्य उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा के उपयोग को रोकना अर्थात, परमाणु प्रसार को रोकना।
(iii) यह सदस्य देशों की नियमित जाँच करता है ताकि कोई इसका गलत प्रयोग न करे।

'उत्तर-10'

विश्व की चार साझी विरासतें - साझी विरासत का अर्थ है जिस पर किसी एक का नहीं बल्कि सभी देशों का अधिकार होता है।

(i) अंतरिक्ष
(ii) अंटार्कटिका
(iii) समुद्र
(iv) वायुमंडल
(v) ओजोन परत

'उत्तर-11'

वैश्वीकरण का अर्थ है देश की अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था से जोड़ना, अर्थात इसमें देश पूंजी, विचार, वस्तुओं के आदान-प्रदान से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं।
विरोध के 2 कारण-

(i) राज्य की क्षमता में कमी - वैश्वीकरण के कारण राज्य की क्षमता में कमी आती है, राज्य स्वयं को केवल मुख्य कार्यों तक सीमित रखते हैं। राज्य के कमजोर होने से उनकी गरीबों की हित की रक्षा करने की शक्ति में कमी होती है,

(ii) सांस्कृतिक समरूपता - इसका अर्थ विश्व संस्कृति का उदय नहीं बल्कि शेष विश्व पर पश्चिमी संस्कृति थोपे जाने से है, जिससे पुरातन संस्कृतियां समाप्त हो रही हैं,

'उत्तर - 12'

केरल मॉडल - केरल में विकास व नियोजन के लिए अपनाया गया मॉडल केरल मॉडल कहलाता है, यह विकेन्द्रिकृत नियोजन का उदाहरण है।

केरल मॉडल में शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, कारगर खाद्य वितरण, गरीबी उन्मूलन पर बल दिया गया,

'उत्तर - 13'

आसियान की दक्षिण पूर्व एशिया के आर्थिक विकास में भूमिका -

(i) आर्थिक समुदाय - आसियान ने आर्थि आसियान आर्थिक समुदाय की स्थापना की ताकि इस क्षेत्र में साझा बाजार तैयार किया जा सके, यह देशों के बीच पूंजी, निवेश व श्रम की आवाजाही बनाए रखता है,

(ii) मुक्त व्यापार क्षेत्र - आसियान ने न केवल सदस्य देशों के बीच व्यापारिक बाधाओं को कम किया बल्कि दक्षिण कोरिया, जापान के साथ भी मुक्त व्यापार समझौते किए ताकि क्षेत्र में आर्थिक निवेश हो,

(iii) विवादों का निपटारा - आसियान ने सदस्य देशों के आर्थिक विवादों

को निपटाने के लिए आर्थिक निवारण तंत्र स्थापित किया है ताकि विदेशी व्यापार में स्थिरता बनी रहे।

'उत्तर-14'

संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। तब विश्व राजनीति में जो सच्चाइयाँ थी उसी के अनुसार इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन शीतयुद्ध के बाद ये परिस्थितियाँ बदल गई हैं। अतः इसमें सुधार आवश्यक है।

सुरक्षा परिषद में 1992 में प्रस्ताव पारित हुआ जिसमें निम्न 3 शिकायतें थी -

(i) सुरक्षा परिषद अब विश्व राजनीति की सच्चाइयों की नुमाइंदगी नहीं करता।

(ii) इसके फैसलों में चंद देशों का दबदबा है।

(iii) सभी को सुरक्षा परिषद में बराबरी का हक नहीं है।

इसमें दो तरह के बदलाव शामिल हैं -

(i) सुरक्षा परिषद के बुनियादी ढाँचे व प्रक्रियाओं में बदलाव

(ii) न्यायाधिकार से जुड़े मामलों में समीक्षा की जाए,

ढाँचे में बदलाव ⇒ इसमें यह माँग की गई है कि सुरक्षा परिषद के स्थायी व अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि राजनीतिक वास्तविकताओं की नुमाइंदगी की जा सके।

(ii) वीटो को सीमित तथा समाप्त किया जाए, क्योंकि एक स्थायी सदस्य किसी भी प्रस्ताव को होने से रोक सकता है।

अतः, विश्व के सभी देशों के समान विकास करने और राजनीति की वास्तविकताओं की नुमाइंदगी के लिए सुरक्षा परिषद के ढाँचे में बदलाव करना जरूरी है।

'उत्तर-15'

क्योटो प्रोटोकल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो वैश्विक तापवृद्धि को नियंत्रित करने के लिए ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए दिशा निर्देश बताता है।
इसके अंतर्गत औद्योगिक देशों के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए लक्ष्य निर्धारित किए हैं, इसमें भारत को छूट दी गई है क्योंकि
(i) विश्व के पर्यावरण को अधिक नुकसान औद्योगिक देशों के कारण हुआ है, अतः ज्यादा भागीदारी भी उनकी है।
(ii) भारत का कॉर्बन डाई ऑक्साइड उत्सर्जन विकसित देशों की तुलना में कई गुना कम है।
(iii) भारत अभी विकास प्रक्रिया से गुजर रहा है अतः उसे अपना विकास करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है।

'उत्तर-16'

कांग्रेस को इसकी समावेशी प्रकृति और सभी को साथ लेकर चलने की क्षमता के कारण सामाजिक व विचारधात्मक गठबंधन कहते हैं। इसके पक्ष में कुछ तर्क निम्न हैं -

(i) समावेशी गठबंधन ⇒ कांग्रेस के ने अपने भीतर दक्षिणपंथी-वामपंथी, चरमपंथी-नरमपंथी, कट्टरपंथी शांतिवादी सभी विचारधाराओं को मानने वालों को स्थान दिया है।
(ii) साझा मंच ⇒ कांग्रेस केवल राजनीतिक दल नहीं है बल्कि एक साझा प्लेटफार्म है जहाँ विभिन्न विश्वासों, आकांक्षाओं को मानने वाले समूह या व्यक्ति एक साथ राष्ट्रीय आंदोलन में भाग ले सकते हैं।
(iii) संगठनात्मक ढाँचा ⇒ कांग्रेस के भीतर स्वतंत्रता से पहले वे संगठन भी शामिल थे जिनका अपना संविधान व संगठन था। उदा- सोशलिस्ट पार्टी

(iv) सहिष्णुता - कांग्रेस की विचारधारा का दायरा इतना बड़ा था कि वह विपक्षी दृष्टिकोण को भी अपने भीतर समाहित कर लेती थी,

'उत्तर-17'

लाल बहादुर शास्त्री जी सिंडिकेट के समर्थन से 1964 से ~~16~~ 1966 तक देश के प्रधानमंत्री रहे, वे इस पद पर बड़े कम समय तक रहे, उन्होंने दो चुनौतियों का सामना किया,

(i) भारत, चीन युद्ध से उत्पन्न आर्थिक संकट से उभरने की कोशिश कर रहा था क्योंकि इस युद्ध के कारण भारत का अधिकांश धन सैन्य खर्च में व्यय हो गया था,

(ii) देश में मानसून असफलता थी, जिसके कारण, कृषि पैदावार में कमी आई, सूखा पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप देश के सामने खाद्यान्न संकट आ खड़ा हुआ, इसके कारण बिहार में अकाल की स्थिति भी उत्पन्न हुई जिससे कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, साथ ही 1965 में भारत-पाक युद्ध भी हुआ जिससे देश की अर्थव्यवस्था गहरा आघात पहुँचा,

'उत्तर-18'

आपातकाल - आपातकाल वह स्थिति है जब सरकार बाहरी और आंतरिक खतरे की स्थिति में लगा सकती है, इसमें सारी शक्तियाँ केंद्र में निहित हो जाती है और मौलिक अधिकार भी निष्क्रिय हो सकते हैं,

आपातकाल की घोषणा के परिणाम - 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की गई थी, जिसके निम्न परिणाम हुए -

(i) विरोध आंदोलन व प्रदर्शन एक बार में रुक गई,

(ii) प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई, समाचार पत्रों को कहा गया,

कुछ भी छापने से पहले अनुमति लें,
(iii) नागरिकों के मौलिक अधिकार निष्क्रिय हो गए अब उन्हें ये अधिकार भी नहीं था कि वे अपने अधिकारों के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाए,
(iv) बड़े पैमाने पर निवारक नजरबंदी की गई, अर्थात, बिना किसी आधार के लोगों को गिरफ्तार किया गया, कुल 676 नेताओं व एक लाख ग्यारह हजार लोगों को गिरफ्तार किया गया,

इसके कुछ सबक भी सीखे गए - (i) भारत से लोकतंत्र विदा कर पाना मुश्किल है। (ii) जनता अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुई। (iii) आपातकाल केवल सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में लगा सकता है।

'उत्तर-19'

1989 के बाद चुनावी गठबंधनों की आवश्यकता व महत्व -
(i) एकदलीय शासन समाप्त - 1989 में कांग्रेस जो आजादी के बाद लगातार बहुमत प्राप्त करती रही, इसमें मात्र 197 सीटें मिली, साथ ही किसी विपक्षी दल को भी पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त था, जिसके कारण सभी दलों ने एक साथ मिलकर गठबंधन बनाया, उदा- के लिए राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार इसे जनता दल व क्षेत्रीय दलों को मिलाकर बनाया गया था,

(ii) क्षेत्रीय दलों की भूमिका - 1989 के बाद राज्यों में क्षेत्रीय दलों का प्रभाव पड़ा, ये राज्य की समस्याओं को अच्छी तरह समझते थे, जिससे राष्ट्रीय दल को सरकार बनाने के लिए इन दलों की सहायता लेनी पड़ती थी।
(iii) विविधता में एकता - भारत विविधताओं वाला देश है जहां विभिन्न क्षेत्रीय आकांक्षाएं होती थी, गठबंधन के कारण ही छोटी-छोटी पार्टियों को सत्ता चलाने का मौका मिला जिससे राज्य की समस्याओं पर केंद्र का ध्यान गया,

'उत्तर-20'

अन्य पिछड़ा वर्ग राजनीति का उदय 1989 की एक मुख्य बदलाव हैं, इसने भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण बदलाव किया,
(i) इससे पिछड़ा वर्ग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुए,
(ii) इसके कारण पिछड़े वर्गों की आकांक्षाओं को समझने में मदद मिला,
(iii) विभिन्न राजनीतिक दलों ने पिछड़े वर्ग की सामाजिक व राजनीति दावे की स्वीकृति दी है, जिससे सत्ता में उनकी भागीदारी पर जोर दिया गया,
(iv) पिछड़ा वर्ग राजनीति के कारण पिछड़ा वर्ग को सभी जगह समानता का अवसर प्राप्त हुआ, जिससे वे समाज में अपनी भागीदारी करने में सुनिश्चित हुए,
(v) पिछड़ा वर्ग राजनीति के कारण जनता के पास विकल्प बढ़ गए थे, अब वे अपने हितों के लिए इन दलों को वोट दे सकते थे,
(vi) इससे पहले पिछड़ा वर्ग की राजनीति को इतना महत्व नहीं दिया गया था।

'उत्तर-21'

सोवियत संघ 1917 की रूस की बोल्शेविक क्रांति के बाद अस्तित्व में आया,
इसका विघटन निम्न कारणों से हुआ
(i) गोर्बाचेव के सुधार नीति - 1985 में सत्ता में आने के बाद गोर्बाचेव ने सुधार की नीति चलाई जिससे सोवियत संघ के विघटन की प्रक्रिया तीव्र हो गई-

(i) पेरेस्त्रोइका - अर्थव्यवस्था को ढील देना व उसे खोलना
(ii) ग्लास्नोस्त - अभिव्यक्ति की आजादी, जिससे जनता ने सरकार की आलोचना करना शुरू कर दिया,

आर्थिक गतिरोध - सोवियत संघ के संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा हथियारों को बनाने के लिए प्रयोग किया जा रहा था, जिसके कारण -
(i) उपभोक्ता वस्तुओं की कमी हुई,
(ii) प्रौद्योगिकी व बुनियादी ढाँचे में पश्चिमी देशों से पीछे हो गए,

प्रशासन भ्रष्टाचार - सोवियत संघ में लंबे समय से कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा रहा, लंबे समय की तानाशाही ने पार्टी को जनता की आकांक्षाओं से बेखबर रखा, जिससे जनता में असंतोष फैला,

जनता की जागरूकता ⇒ संचार क्रांति के कारण जब जनता को यह ज्ञात हुआ कि पश्चिमी देश के लोग उनसे बेहतर जीवन जी रहे हैं तो उनमें भी असंतोष पनपा जिससे उन्होंने उसके विघटन की माँग की,

बर्लिन दीवार का गिरना - 4 नवंबर 1989 को जनता द्वारा बर्लिन की दीवार को गिरा दिया जो साम्यवाद और पूंजीवादी देशों के बीच विभाजक का प्रतीक थी,

विघटन ⇒ अन्ततः 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया,

परिणाम - सोवियत संघ के विघटन के निम्न परिणतियाँ हुआ-

(i) विश्व एक ध्रुवीय अर्थात, अमेरिकी वर्चस्व स्थापित हो गया,
(ii) सोवियत संघ और अमेरिका के बीच चल रहे हथियारों के होड़ की समाप्ति हुई,

(iii) सोवियत संघ का विघटन और 15 नए राज्यों का गठन जिन्होंने स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल बनाया,
(iv) शीतयुद्ध का अंत
(v) विश्व राजनीति में शक्ति संबंधों में परिवर्तन,
(vi) समाजवाद का वर्चस्व स्थापित,
(vii) समाजवादी देशों द्वारा शॉक थेरेपी अपनाना,

'उत्तर -२२'

भारत का विभाजन 14-15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को बड़ी कठिन चुनौतियों में हुआ था, देश की जनसंख्या का स्थानान्तरण, महिलाओं का शोषण, सांप्रदायिक हिंसा इसी के परिणाम थे, स्वतंत्र भारत के समक्ष तीन चुनौतियां था -

(i) राष्ट्रीय एकता की चुनौती ⇒ भारत विविधताओं (भाषा, धर्म, संस्कृति) वाला देश है, ऐसे में विविधताओं के साथ एकता बनाए रखना एक चुनौती थी, भारत आकार और विविधताओं में किसी महादेश के बराबर था ऐसे में विविधताओं के साथ क्षेत्रीय और उपक्षेत्रीय पहचान बनी रहेगी, यह प्रश्न चुभता हुआ था, देसी रियासतों का भारतीय संघ में विलय भी इसी की चुनौती थी, भारत में 565 देसी रियासतें थी, स्वतंत्रता के बाद इन्हें आजादी थी कि चाहे तो वे भारत में जा सकते हैं या पाकिस्तान में, ऐसे में अखण्ड भारत का सपना धूमिल होता दिख रहा था,

(ii) लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती ⇒ हालांकि संविधान सभा ने हमें एक लोकतांत्रिक संसदीय शासन प्रणाली, मौलिक अधिकारों और चुनाव आयोग से बंधा संविधान उपहार में दिया था, किंतु इतना

काफी नहीं था, असली चुनौती यह थी कि लोकतंत्र से मिलते जुलते नियम प्रचलन में लाए जाए, देसी रियासतों का बाद में विलय तो कर लिया गया लेकिन यहां चुनौति यह थी कि इन्हें प्रजातंत्रीय सांचों में ढाला जाए, क्योंकि यहां स्वतंत्रता से पहले राजाओं का शासन होता था।

(iii) विकास की चुनौती ⇒ तीसरी और सबसे बड़ी चुनौति विकास की थी, ऐसा विकास जिससे समाज के सभी लोगों का भला हो, सरकार का मानना था कि एक गरीब और आर्थिक रूप से पिछड़ा समाज कभी सुरक्षित नहीं रह सकता है, क्योंकि गरीबी लोगों को अनैतिक कार्य जैसे चोरी डकैती करने ~~से रोकती है~~ के लिए प्रेरित करती है, अब चुनौति गरीबी को खत्म करने के लिए कारगार नीतियां और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए नीतियां तैयार करना है।

'उत्तर-23'

पृष्ठभूमि - नेपाल अतीत में एक संवैधानिक राज्य था फिर भी आधुनिक काल में लंबे समय तक यहां राजा का शासन स्थापित था, राजतंत्र के समय वहां की राजनीतिक पार्टियां और जनता ने अधिक उत्तरदायी शासन की मांग की।

जनता की मांग ⇒ एक मजबूत लोकतंत्र समर्थक की चपेट में आकर ~~सरकार~~ राजा ने 1990 में लोकतांत्रिक सरकार चलाने की अनुमति दे दी, नेपाल की पार्टियों का कार्यकाल बहुत ही छोटा और कठिनाइयों से भरा हुआ था।

माओवादियों का प्रभाव - 1990 में माओवादी नेपाल के कई हिस्सों में अपना ~~प्र~~ प्रभाव जमाने के सफल हुई, ये राजा और संसद के कार्यकर्ताओं को उनके पद से हटाना चाहते थे, जिस कारण राजा की सेना और माओवादियों के बीच संघर्ष छिड़ गया, कुछ समय तक राजा, माओवादी और लोकतंत्र के समर्थकों के बीच त्रिकोणीय संघर्ष चला,

संसद भंग ⇒ इन कारणों से राजा ने संसद को 2002 में भंग कर दिया, इस कारण नेपाल में जो बचा कुचा लोकतंत्र था वह भी नष्ट हो गया,

जन आंदोलन - 2006 में नेपाल की जनता ने फिर लोकतंत्र स्थापित करने के लिए एक आंदोलन किया, इसका आंदोलन का नेतृत्व सेवेन पार्टी अलायंस और माओवादी तथा समाजिक कार्यकर्ता कर रहे थे, हालांकि माओवादी और सेवेन पार्टी अलायंस एक दूसरे के कट्टर विरोधी थे किंतु नेपाल में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए उन्होंने हाथ मिलाया,

लोकतंत्र स्थापना ⇒ जन आंदोलन में लाखों लोग सड़कों पर उतर आए व उन्होंने कर्फ्यू का पालन करने से मना दिया, जिससे देश की शासन व्यवस्था ठप्प पड़ गई थी, जनता के इतने बड़े साहस के कारण सेना भी उन पर हथियार उठाने से हिचकिचाए, क्योंकि आंदोलन इतना मजबूत था कि यदि सेना रोकने का प्रयास भी करती तो भी न रुकता, अंतत: नेपाल 2006 में स्वतंत्र हुआ और वहां लोकतंत्र स्थापित हुई, नेपाल ने 2008 में संविधान बनाया,

'उत्तर-24'

गुटनिरपेक्षता ⇒ गुटनिरपेक्षता का अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किसी भी गुट में शामिल होने के बजाय स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करना, भारत ने भी शीतयुद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ में शामिल न होकर स्वतंत्र विदेशनीति अपनाई थी - भारत की गुटनिरपेक्षता नीति वर्तमान संदर्भ में निम्नवत हैं -

(i) स्वयं निर्णय लेने की शक्ति - गुटनिरपेक्षता के कारण ही भारत बिना किसी बाहरी शक्ति के दबाव के अपने निर्णय ले सकता है, अर्थात, भारत वही करता है जो उसके हित में हो ना कि जो दूसरों द्वारा बताया जाए,

(ii) विश्व शांति का समर्थन ⇒ भारत ने सदैव विश्व शांति का समर्थन किया है, भारत विवादों का हल युद्ध द्वारा नहीं बल्कि विचार-विमर्श द्वारा करने के समर्थन में होता है, वर्तमान में भी यदि किन्हीं दो देशों के बीच युद्ध होता है उदा. रूस और यूक्रेन तो भारत किसी एक पक्ष का अंधा समर्थन करने के बजाय विश्व शांति और बातचीत को बढ़ावा देता है,

(iii) सबसे दोस्ती ⇒ भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति सबसे दोस्ती की रही है, अर्थात, भारत एक ओर अमेरिका से व्यापार बढ़ा रहा है तो दूसरी ओर रूस जैसे परम्परागत मित्र से तेल और हथियारों का आयात बढ़ा रहा है,

(iv) विकासशील देशों की सहायता ⇒ भारत गुटनिरपेक्षता नीति के कारण ही विकासशील देशों की मदद कर पाता है, उदा के लिए कोरोना के समय वैक्सिन देना या जलवायु परिवर्तन के मामले में उनकी बात उठाना,

(v) राष्ट्रीय हित की सुरक्षा - आज भारत की गुटनिरपेक्षता

की नीति केवल बातों की नहीं है बल्कि यह अपनी गुटनिरपेक्षता को सुदृढ़ बनाने के लिए कठोर कदम उठाता है, लेकिन किसी गुट में शामिल नहीं होता है।

(vi) स्वतंत्र पहचान ⇒ भारत एक विशाल देश है जिसका विशाल इतिहास व संस्कृति है, भारत गुटनिरपेक्षता के कारण ही अपनी स्वतंत्र पहचान बनाने में सक्षम रहा और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अपनी बात रखने में समर्थ हुआ, यह विकासशील देशों के नेता के रूप में उभर रहा है।

'उत्तर - 25'

हर क्षेत्रीय आंदोलन अलगावादी मांग की तरफ नहीं होता बल्कि अपनी संस्कृति, भाषा और पहचान को बचाने के लिए होता है। जिसे निम्न उदाहरणों से समझा जा सकता है -

असम आंदोलन - असम आंदोलन 1979 से 85 तक बाहरी लोगों के खिलाफ चला था।

असम में बड़ी संख्या में आप्रावासी आ रहे थे, असम के लोगों के मन में बाहरी लोगों के खिलाफ गुस्सा था जिसके निम्न कारण थे -

(i) संस्कृति को लेकर डर - असम के लोगों को डर था कि अगर इसी तरह बाहरी लोग असम में बसते रहे तो उनकी भाषा, संस्कृति और पहचान खत्म हो जाएगी।

(ii) आर्थिक पिछड़ेपन ⇒ असम में तेल, कोयला, चायपत्ती खनिज जैसे प्राकृतिक संसाधन भरपूर थे फिर भी वह आर्थिक रूप से पिछड़ा था, इस क्षेत्र के लोगों को लगा कि इनके संसाधन बाहर भेजे जा रहे हैं।

मॉंग ⇒ इनकी मॉंग थी कि 1951 के बाद जितने भी लोग भारत आए हैं उन्हें पहचानकर वापिस उनके देश भेजा जाए, अन्ततः 1985 में असम समझौता हुआ, जिस पर सहमति बनी कि 1971 के बाद जितने भी लोग भारत आए हैं उन्हें पहचानकर वापस भेजा जाए,

द्रविड़ आंदोलन ⇒ द्रविड़ आंदोलन भारत के क्षेत्रीय आंदोलनों में सबसे प्रबल आंदोलन था, इसमें एक पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कषगम थी, जिसने ब्राह्मणों के वर्चस्व का विरोध किया व क्षेत्रीय गौरव पर जोर दिया, इनकी मॉंगे निम्नवत थी -

(i) कल्लकुडी रेलवे स्टेशन का नाम डालमियापुरम किया जाए,

(ii) इसमें तमिल संस्कृति इतिहास को स्कूली पाठ्यक्रम में पढाने की बात की गई,

(iii) राज्य सरकार के शिल्पकर्म शिक्षा कार्यक्रम को लेकर थी,

~~असम की~~ स्वायत्त मॉंग ⇒ आजादी से पहले ~~असम~~ त्रिपुरा और मणिपुर को छोड़कर सभी असम कहलाता था, जब गैर असमी लोगों ने महसूस किया कि सरकार उन पर गैर असमी भाषा थोप रही है तो उन्होंने स्वायत्त की मॉंग करना शुरू कर दिया,

मॉंग ⇒ उनकी मॉंग थी कि असम को काटकर छोटे-छोटे राज्य बना दिए जाए, अंततः असम को काटकर मेघालय, नागालैण्ड बनाए गए,

जम्मू कश्मीर की क्षेत्रीय आकांक्षाएं - जम्मू कश्मीर में तीन भाग आते हैं - जम्मू, कश्मीर और लद्दाख

(i) जम्मू - जम्मू में अधिकांश हिन्दू रहते हैं और इन्होंने अपने विकास व राजनीति में ज्यादा हिस्सेदारी की मॉंग की,

(ii) कश्मीर - कश्मीर में अक्सर स्वायत्ता की मॉंग उठती है, इनके हिसाब से जो स्वायत्ता दी गई थी वह भारत सरकार द्वारा कम की जा रही है

(iii) लद्दाख - लद्दाख में बौद्ध व शिया रहते हैं जो अपनी संस्कृति को बचाने के लिए जम्मू कश्मीर को केंद्रशासित राज्य का दर्जा देने की बात करते हैं,

P.T.O

'उत्तर-26'

(क)

(i) निरस्त्रीकरण - अर्थात कोई भी देश (राज्य) चाहे उसका आकार, ताकत और प्रभाव कुछ भी हो कुछ खास अस्त्रों के प्रयोग से बाज आए, अर्थात हथियारों के,

(ii) अस्त्र नियंत्रण - अस्त्रों के प्रसार पर नियंत्रण करना, (परमाणु हथियारों)

(iii) विश्वास बहाली, अर्थात, देशों के बीच सुरक्षा मामलों में सूचना का आदान प्रदान,

'उत्तर-26 ख'

निरस्त्रीकरण का अर्थ होता है कि कोई भी राज्य चाहे उसका आकार, प्रभाव या ताकत कुछ भी हो, खास किस्म के हथियारों का प्रयोग न करे, इसमें इन हथियारों के निर्माण की अनुमति नहीं होती व ना ही रखने की अनुमति होती है।
अस्त्र नियंत्रण में परमाण्विक हथियार बनाने की अनुमति होती है लेकिन कुछ नियम और कानूनों का पालन करना पड़ता है,

'उत्तर-26 ग'

BWC (जैविक हथियार संधि) 1972 में जिसमें 155 से ज्यादा देशों ने हस्ताक्षर किए,

CWC (रासायनिक हथियार संधि) 1992 जिसमें 181 देशों ने हस्ताक्षर किए,

'उत्तर-26 घ'

अमेरिका और सोवियत संघ परमाणु हथियारों के विकल्प नहीं छोड़ना चाहती थी। अतः अस्त्र नियंत्रण अपनाया, उन्होंने ऐसा अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने के लिए किया था।

'उत्तर-26(ङ)'

विश्वास की बहाली का अर्थ है - देशों के बीच सुरक्षा मामलों में सूचना का आदान प्रदान। इसमें देश एक-दूसरे को सैन्य गतिविधि व सूचना का आदान-प्रदान करते हैं ताकि गलतफहमी या अचानक युद्ध की स्थिति न बने